डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 मार्च से 31 मार्च, 2022, डिस्पेच दिनांक 16 मार्च, 2022

| वर्ष 65 | अंक 20 | भोपाल | 16 मार्च, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

ड्रोन इस्तेमाल में बनायेंगे मध्यप्रदेश को नम्बर वन : श्री चौहान

प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया उदघाटन

केन्द्रीय मंत्री द्वय श्री तोमर, श्री सिंधिया सहित राज्य सरकार के मंत्री भी रहे शामिल

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्म- निर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिये सरकार सभी दिशाओं में काम कर रही है। इस दिशा में प्रदेश में ड्रोन तकनीक को भी प्रमुखता से अपनाया गया है। हम मध्यप्रदेश को ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल में नम्बर वन राज्य बनायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान गुरूवार को ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल के उदघाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एमआईटीएस मैदान में रिमोट के जरिए ड्रोन उड़ाकर प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर के माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (एमआईटीएस) में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल और एमआईटीएस के नवनिर्मित बॉयज हॉस्टल का उदघाटन किया। खजुराहो सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी. डी. शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकासएवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, अन्य मंत्रिगण, सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कमल माखीजानी सहित जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खुशी की बात है केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर प्रदेश में पाँच ड्रोन स्कूल खुलने जा रहे हैं। इनमें से आज पहले स्कूल का शुभारंभ ग्वालियर में हो गया है। राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति बनाई है, जिसमें युवाओं के नवाचारों को धरातल पर लाने में सरकार भरपूर आर्थिक और तकनीकी मदद मुहैया करायेगी। उन्होंने कहा कि इंदौर के विद्यार्थियों ने नए – नए स्टार्टअप शुरू कर 800 से 1000 करोड़ तक की कंपनियाँ विकसित कर ली हैं। सरकार की स्टार्टअप नीति का लाभ उठाकर ग्वालियर के युवा भी नए-नए स्टार्टअप खड़े कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दोहराया कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनें।

ड्रोन कृषि नीति का लाभ उठाकर आत्म-निर्भर बनने के लिये आगे आएँ युवा : केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में कृषि के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। निकट भविष्य में इस तकनीक के इस्तेमाल से क्रांतिकारी प्रगति सामने आयेगी। उन्होंने कहा भारत सरकार के कृषि विभाग ने ड्रोन नीति जारी कर दी है, जिसमें 12वीं पास बच्चे 4 लाख रूपए तक का अनुदान प्राप्त कर ड्रोन पायलट के रूप में अच्छा रोजगार पा सकते हैं। इसी तरह यदि कृषि स्नातक ड्रोन तकनीक की कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो वह 5 लाख तक का अनुदान पा सकते हैं। इसके अलावा संस्थान भी कृषि ड्रोन नीति में 100 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। श्री तोमर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मकान का मालिकाना हक दिलाने में ड्रोन तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी तरह टिड्डी दल के आक्रमण को असफल करने में ड्रोन तकनीक क्रांतिकारी साबित हुई है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

सभी शासकीय कैंटीन का संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में किया दीदी कैफे का शुभारंभ ● प्रदेश में शुरू हुए 127 दीदी कैफे

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की सभी शासकीय कैंटीन का संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जायेगा। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए आज प्रदेश में 127 दीदी कैफे का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में निर्मित "दीदी कैफे" का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने दीदी कैफे का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह आनंद और गौरव का क्षण है कि हमारी बहनें स्वयं आत्म-निर्भर बनने के साथ आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। स्व-सहायता समूह की बहनों की सफलता में मध्यप्रदेश की भी उन्नति और प्रगति निहित है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, सरकार सदैव हर संभव मदद के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व-सहायता समूह की बहनों को शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि बहनें इतनी आत्मीयता और प्रेम से चाय और नाश्ता बनाती हैं कि इसका स्वाद स्वमेव ही बढ़ जाता है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

लहसुन उत्पादन में मध्यप्रदेश सबसे आगे

नई दिल्ली । देश एवं प्रदेश में महत्वपूर्ण मसाला फसल लहसुन का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 31 लाख 84 हजार मीट्रिक टन हुआ है। इसमें म.प्र. सबसे आगे है। यहां 1 लाख 90 हजार हेक्टेयर में 19 लाख 56 हजार टन उत्पादन हुआ है जो सर्वाधिक है। म.प्र. पिछले तीन वर्षों में भी शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। यह जानकारी गतदिनों लोकसभा में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने दी।

श्री तोमर ने बताया कि देश में म.प्र., राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम प्रमुख लहसुन उत्पादक राज्य है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

वित्तीय प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है वर्ष 2022-23 का बजट – मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे संतु निरामय:, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, के भाव से बनाया गया है। यह वित्तीय प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य बनाते हुए बेहतर वित्तीय प्रबंधन से ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा बधाई के पात्र हैं, यह बजट स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद बजट पर अपना अभिमत व्यक्त करते हुए विधानसभा में मीडिया प्रतिनिधियों से यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की विकास दर करंट रेट पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर देश में सर्वाधिक है। प्रदेश 19.7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर अर्जित करने में सफल रहा है। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रस्तुत बजट आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का बजट है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के वैभवशाली, गौरवशाली, सम्पन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के स्वप्न और संकल्प को पूर्ण करने का बजट है।

राशन, आवास, बच्चों की पढ़ाई और इलाज की व्यवस्था के लिए किए गए हैं विशेष प्रावधान

हर घर में नल से जल के लिए 06 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सर्वस्पर्शी बजट है, क्योंकि यह गरीब कल्याण का बजट है। गरीबों को राशन मिलता रहे, हर गरीब का पक्का मकान बने, हर गरीब के घर पीने का पानी पहुँचे, गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। एक ही वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण के लिए दस हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है, जो संभवत: इतिहास में पहली बार हुआ है। हर घर में नल से जल के लिए जल जीवन मिशन में 06 हजार करोड़ अधिक का प्रावधान राज्य सरकार के गरीब कल्याण के संकल्प को व्यक्त करता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब बीमारी में इलाज करा पाएँ, इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गरीबों के लिए संबल योजना वरदान है। बजट में संबल योजना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

खाद, बीज और ऋण की उपलब्धता और मिलेट मिशन एवं प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रावधान

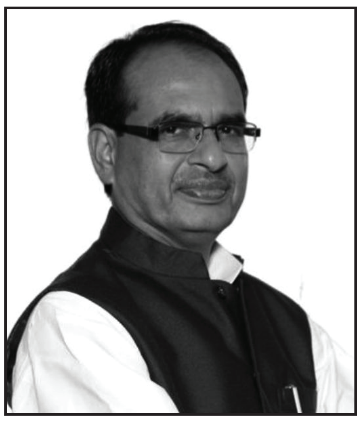

पशुपालन, उद्यानिकी, खाद्य प्र-संस्करण, मछली पालन के लिए 20 हजार 27 करोड़ रूपए की व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब-कल्याण के साथ यह किसानों के कल्याण का भी बजट है। किसानों को 07 हजार 618 करोड़ रूपए फसल बीमा योजना में दिए गए हैं। इसके पहले किसानों को आरबीसी 6-4 में 03 हजार करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए थे। किसानों को बिजली की सब्सिडी की निरंतरता के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही फसल हानि पर राहत के लिए भी व्यवस्था की गई है। किसानों के उत्पाद खरीदने के साथ मिलेट मिशन हो या प्राकृतिक और जैविक खेती, कृषि उत्पादक संगठन हो या फसल निर्यात को प्रोत्साहन, किसानों के लिए खाद-बीज और ऋण की उपलब्धता हो या सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण का विषय, किसान के हित के लिए बजट में सभी बिन्दुओं का ध्यान रखा गया है। पशुपालन, उद्यानिकी, खाद्य प्र-संस्करण, मछली पालन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 20 हजार 27 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है।

> **सबके सुखी, निरोगी रहने और सबके कल्याण के भाव से बनाया गया है बजट**
>
> **यह सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट**
>
> **प्रदेश 19.7 प्रतिशत से अधिक विकास दर अर्जित करने में रहा है सफल**
>
> **यह आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का बजट है**
>
> **प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को गति देगा बजट**

पुन: आरंभ की जा रही कन्या विवाह योजना

जेण्डर बजटिंग में महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं में 84 हजार 512 करोड़ रूपए का प्रावधान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह महिलाओं के उत्थान का बजट भी है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में लगभग 1400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए आजीविका मिशन में भी विशेष व्यवस्था की गई है। कन्या विवाह योजना पुन: आरंभ की जा रही है। उद्यमिता सहित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएँ आगे बढ़ें, इसके लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जेण्डर बजटिंग की दृष्टि से विभिन्न विभाग की अलग-अलग योजनाओं में 84 हजार 512 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

बाल-कल्याण के लिए 57 हजार 803 करोड़ रूपए की व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह बजट बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण का बजट है। राज्य सरकार ने इस वर्ष चाइल्ड बजट की बात कही थी। बच्चों के कल्याण से संबंधित योजनाओं, उनके स्वास्थ्य, पोषण, बेहतर शिक्षा आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीएम राइज स्कूल के लिए 07 हजार करोड़ रूपए अलग-अलग चरणों में व्यय किए जाएंगे। बाल-कल्याण के लिए कुल 57 हजार 803 करोड़ रूपए का प्रावधान है।

कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था

अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 19 हजार 20 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 26 हजार 941 करोड़ रूपए का प्रावधान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग के गरीब हों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति, सभी के सहयोग और कल्याण का बजट में ध्यान रखा गया है। अनुसूचित जाति उपयोजना में 19 हजार 20 करोड़ रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 26 हजार 941 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जातियों के लिए भी बजट में व्यवस्था है।

बजट में किया गया है कर्मचारी-कल्याण पर फोकस

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट में कर्मचारियों के कल्याण पर फोकस किया गया है। महंगाई भत्ता 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है। संभवत: यह एक साथ की गई सबसे बड़ी बढ़ोत्तरी है।

अधोसंरचना निर्माण के लिए 48 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान – रोजगार के अवसर होंगे सृजित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधो-संरचना विकास से अर्थ-व्यवस्था को गति मिलती है। अधो-संरचना के लिए 48 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को गति देगा। सड़कों के निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, ऊर्जा, विशेषकर नवकरणीय ऊर्जा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अधो-संरचना निर्माण से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

बजट में दिया गया है लोक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा गया है। नए चिकित्सालय, जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वेलनेस केन्द्र के सुदृढ़ीकरण तथा इलाज और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण, सभी वर्गों के कल्याण, अधो-संरचना निर्माण और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बना यह बजट स्वागतयोग्य है।

शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए अप्रैल माह से : मुख्यमंत्री श्री चौहान

> **लाड़ली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश पर देंगे 25 हजार रूपये की एक मुश्त राशि**

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अप्रैल माह से शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं को कॉलेज में प्रवेश लेने पर एक मुश्त 25 हजार रूपये की सहायता राशि और दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान विदिशा जिला मुख्यालय स्थित श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर उनके जन्म-दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

महिला सशक्तिकरण में मध्यप्रदेश ने रचा नया इतिहास : मुख्यमंत्री श्री चौहान

महिला वित्त विकास निगम का होगा सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से स्थापित होगा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष

मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना होगी प्रारंभ

इंदौर और भोपाल में महिला उद्यम प्रोत्साहन के लिये बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क

महिला सशक्तिकरण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी : सांसद श्री जे.पी. नड्डा

पोषण आहार संयंत्र महिला सशक्तिकरण को नई दृष्टि और दिशा देगा

प्रधानमंत्री श्री मोदी के पोषण अभियान के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश आगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं सांसद श्री नड्डा ने देवास में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी पोषण आहार संयंत्र की चाबी

महिला स्व-सहायता समूहों को 300 करोड़ रूपये का ऋण वितरित

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देवास में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने महिला सशक्तिकरण में नया इतिहास रचा है। मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन में महिलाओं के स्व-सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में क्रांति की है। आज महिला स्व-सहायता समूह पोषण आहार निर्माण, गणवेश निर्माण, फ्लाई एश से ईंट निर्माण, समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी, राशन दुकानों का संचालन आदि अनेक कार्य कर रहे हैं। देवास में आज प्रारंभ किये जा रहे पोषण आहार संयंत्र में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। प्रदेश में महिला वित्त विकास निगम का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, दूसरा-प्रदेश में 100 करोड़ रूपये की लागत से मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष स्थापित होगा, तीसरा-मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना प्रारंभ होगी और चौथा-इंदौर एवं भोपाल में महिला उद्यम प्रोत्साहन के लिये इंडस्ट्रियल पार्क बनाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं सांसद श्री जे.पी. नड्डा ने देवास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला स्व-सहायता समूहों को पोषण आहार संयंत्र की चाबी सौंपी। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 300 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया। जल जीवन मिशन में कार्य करने के लिये महिलाओं को टूल किट प्रदाय किये गये। महिलाओं के संकुल स्तरीय संगठनों को पुरस्कृत किया गया। स्व-सहायता समूह की सफलता की कहानियों की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ बेटियों के पूजन के साथ हुआ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश में अदभुत कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री आवास की महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री, उज्ज्वला कनेक्शन, राशन प्रदाय, आजीविका मिशन आदि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश आगे है। मध्यप्रदेश में पैदा होने से अंतिम साँस लेने तक बहन-बेटियों का पूरा ध्यान सरकार रखती है। प्रदेश में 41 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मी है, जो पैदा होते ही लखपति हो जाती है। बेटियों के कॉलेज में प्रवेश पर उन्हें 25 हजार रूपये तथा प्रतिवर्ष 5 हजार रूपये अध्ययन के लिए दिये जा रहे हैं। साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि पाठ्यक्रमों की फीस भी सरकार भरती है। आगामी अप्रैल माह से बेटियों की शादियाँ सरकार धूमधाम से करायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिये मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव एवं शासकीय शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण तथा पुलिस विभाग में 30 प्रतिशत एवं अन्य भर्तियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाएँ आगे बढ़े-तरक्की करें, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का पूरा आशीर्वाद है। आपका भाई शिवराज आपके साथ खड़ा है।

सांसद श्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। पहले ठेकेदारों के माध्यम से पोषण आहार बनता था। अब प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह यह कार्य करेंगी। यह महिला सशक्तिकरण को नई दृष्टि एवं दिशा देगा। महिलाएँ यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 800 करोड़ रूपये का कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिये वर्ष 2018 में पोषण अभियान की शुरूआत की थी। इसके माध्यम से बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार प्रदान कर सशक्त किया जा रहा है। देश में 74 लाख स्व-सहायता समूह गठित किये गये हैं, जिनमें 8 करोड़ बहनें कार्य कर रही हैं। मध्यप्रदेश में साढ़े तीन लाख स्व-सहायता समूह में 40 लाख बहने कार्य कर रही हैं। प्रदेश में आगामी 3 वर्षो में 25 लाख बहनें स्व-सहायता समूह से और जुड़ेंगी। महिला समूहों को एक वर्ष में 2525 करोड़ रूपये का ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जायेगा। यह निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को नये आयाम देगा।

सांसद श्री नड्डा ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला-पुरूष अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले एक हजार पर 918 बेटियाँ पैदा होती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 958 हो गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को 6 माह का प्रसूति अवकाश एवं 6 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही मुफ्त ईलाज दिया जाता है। महिलाओं के सम्मान के लिये सरकार कृत-संकल्पित है। देश में 11 करोड़ इज्जत घर (शौचालय) एवं मध्यप्रदेश में 66 लाख इज्जत घर बनाये गये हैं। मध्यप्रदेश में 3 करोड़ 70 लाख महिलाओं को जन-धन खातों से जोड़ा गया है।

श्री नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है तथा उस तरक्की में महिलाओं की अहम भूमिका है।

मजदूर से बनी मालिक

प्रारंभ में पोषण आहार संयंत्र की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा बाई परमार ने कहा कि पहले मैं मजदूर का कार्य करती थी। वर्ष 2017 से आजीविका मिशन में स्व-सहायता समूह बनाकर कार्य प्रारंभ किया। आज मैं मजदूर से मालिक बनी हूँ। कार्यक्रम में श्रीमती दुर्गाबाई परमार एवं श्रीमती अंतर बाई चौहान ने संयंत्र में निर्मित पोषण आहार के पैकेट्स अतिथियों को भेंट किये।

कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता श्री मुरलीधर राव, प्रभारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, सांसद श्री वी.डी. शर्मा, सांसद श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार उपस्थित थी।

प्रदेश की मण्डियों को अत्याधुनिक, सर्वसुविधायुक्त बनायें : मंत्री श्री पटेल

मण्डी समिति हरदा को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित किया जायेगा

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश की मण्डियों को अत्याधुनिक, सर्वसुविधायुक्त बनाया जायें। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 138वीं बैठक में उक्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मण्डियों के आधुनिक होने पर कृषकों को मण्डियों में असुविधा नहीं होगी। उन्होंने आधुनिक बनाने के लिए समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये। बैठक में मंत्री श्री पटेल ने मण्डी समिति हरदा को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्री श्री पटेल ने वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट, जिसमें आय शीर्ष में राशि रूपये 241.70 करोड़ की सकल प्राप्ति एवं व्यय शीर्ष में राशि रूपये 241.50 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया। उन्होंने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड (ए.आई.एफ.) के तहत मध्य प्रदेश की मंडियों को जोड़ कर कृषि अधोसंरचना के निर्माण को सुदृढ किये जाने के प्रस्ताव पर भी सहमती दी। मंत्री श्री पटेल ने प्रदेश की मण्डियों में राज्य विपणन विकास नियम निधि – 2000 के अंतर्गत निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्रदान की। मंत्री श्री पटेल ने मण्डी बोर्ड के प्रशासनिक भवन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया और मण्डी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों एवं मुख्यालय के लिए किराये पर वाहनों को लेने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी।

संचालक मण्डल की बैठक में मंडी बोर्ड उपाध्यक्षा सुश्री मंजू राजेंद्र दादू, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री विकास नरवाल उपस्थित रहे।

सभी साँची पार्लरों में रखी जाएगी दूध टेस्टिंग किट

भोपाल : प्रबंध संचालक एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन श्री संजय गुप्ता ने दुग्ध संघ के सभी पार्लर्स में 'मिलावट से मुक्ति अभियान' में दूध की टेस्टिंग किट रखवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा इससे ग्राहक निर्धारित शुल्क देकर दूध की टेस्टिंग करवा सकेंगे और गुणवत्ता के प्रति पूर्ण आश्वस्त रहेंगे।

श्री गुप्ता ने कहा कि दुग्ध संघ द्वारा निर्मित उत्पाद और विक्रय किये जा रहे दूध की हमेशा ही उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। श्री गुप्ता ने यह निर्देश डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए दिए।

प्रबंध संचालक ने कहा कि प्रदेश के आमजन तक अधिकतम साँची उत्पाद और दूध पहुँचाने के लिए नई एजेंसियाँ शुरू की जाएंगी। उन्होंने दुग्ध संघ को अपने खर्चों में कटौती करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने साँची दूध, मक्खन और आईस्क्रीम का उत्पादन बढ़ाने को कहा।

श्री गुप्ता ने कहा कि शासन के प्रयासों से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या में भी वृद्धि करें। ग्राम स्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी विभाग की विभिन्न योजनाएँ-टीकाकरण, टेगिंग, इनॉफ पंजीकरण, पशु बीमा, हरा चारा बीज, पशु चिकित्सा आदि का प्रभावी क्रियान्वयन करें।

जैविक खेती से किसानों की तकदीर बदलेगी - कृषि मंत्री श्री पटेल

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हाटपीपल्या कृषि उपज मण्डी में तीन दिवसीय कृषि जैविक मेले का शुभारम्भ् करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है। प्रदेश सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएँ संचालित कर रही है। केन्द्र और प्रदेश सरकार किसान भाईयों की आय दोगुना करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जैविक खेती से किसान भाईयों की तकदीर बदलेगी। किसान भाई जैविक खेती को अधिक से अधिक अपनायें।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि देवास जिले में एक लाख 30 हजार हेक्टेयर भूमि पर माइक्रो उद्यम सिंचाई योजना को प्रदेश सरकार ने मंजूर किया है। इससे विकासखण्डं बागली और हाटपिपल्याह के किसान लाभान्वित होंगे। योजना से देवास विकासखण्ड के भी कुछ गाँवों के किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने आव्हान किया कि किसान गौवंश को पालें और गोबर एवं गौ-मूत्र का प्राकृतिक खेती में उपयोग करें। किसान भाई एफपीओ बनायें। किसानी के साथ-साथ व्यापार भी करें। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कृषि जैविक मेले में लगाये गये जैविक उत्पादों के स्टॅानलों का अवलोकन भी किया।

कृषि जैविक मेला 6 मार्च तक रहेगा। कृषि जैविक मेले में किसानों को शासन की योजनाओं, खेती की नई तकनीक और जैविक खेती के संबंध में जानकारी दी जायेगी। किसानों को जैविक खेती के लाभ बताये जायेंगे और जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जायेगा। मेले में विधायक खातेगांव श्री आशीष शर्मा, विधायक हाटपिपल्याक श्री मनोज चौधरी, श्री राजीव खण्डेलवाल सहित अन्यश जन-प्रतिनिधि, भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी एवं किसान भाई उपस्थित थे।

केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में म.प्र. को 1279 करोड़ रुपये आवंटित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत का माना आभार

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1279 करोड़ 20 लाख रुपये का आवंटन दिया गया है। इससे "हर घर-शुद्ध पेयजल" के संकल्प की सिद्धि के प्रयासों को नई गति मिलेगी, जिससे लाखों परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश को जल जीवन मिशन में राशि आवंटन करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार माना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत के मार्गदर्शन में हर परिवार के घर तक नल से जल पहुँच रहा है। मध्यप्रदेश के निवासियों का जीवन बदलने में प्रधानमंत्री श्री मोदी के सहयोग के लिए प्रदेशवासी हृदय से आभारी हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिशन से हर गाँव में पेयजल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 45 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्रांश और 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जा रही है। अभी तक जिन 4 हजार से अधिक ग्रामों में मिशन की परियोजना लागू हुई है, उसके संचालन एवं संधारण का काम ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण परिवारों से मिशन का लाभ लेने और पानी के संरक्षण पर ध्यान देने को भी कहा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार गाँव की सूरत बदलने का काम कर रही हैं। गाँव में पेयजल की सहज उपलब्धता के लिये प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल- जीवन मिशन की सौगात दी है, जो विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिये वरदान साबित हो रही है। मिशन से प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचलों में एकल और समूह पेयजल योजना बनाकर युद्ध-स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिशन से अब तक 4 हजार से अधिक ग्रामों के हर घर में और 46 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवा दिया गया है। जल की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित राशि से मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में मिशन का बेहतर क्रियान्वयन कर रहे मध्यप्रदेश के 47.14 लाख (39%) ग्रामीण परिवारों को लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी का उद्देश्य देश में "हर घर जल" सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के जल जीवन मिशन ने अब क्रांतिकारी जन-आंदोलन का रुप ले लिया है।

संग्रहित लघु वनोपज की निर्वतन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए : वन मंत्री डॉ.शाह

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की हुई बैठक

भोपाल : वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहित लघु वनोपज के निर्वतन प्रक्रिया को सरलीकृत बनाया जाए। इससे राज्य लघु वनोपज की आय में वृद्धि होने के साथ इस कार्य में जुड़े गरीब तबके को फायदा मिल सकेगा। डॉ. शाह मंत्रालय में वनोपज अन्तर्विभागीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

वन मंत्री डॉ.शाह ने निर्देश दिए कि संग्रहित लघु वनोपज की नीलामी प्रक्रिया में जिला स्तर पर अधिकार प्रत्यायोजित किए जाएँ, जिससे लघु वनोपज की नीलामी प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी की जा सके।

राज्य लघु वनोपज के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने बताया कि केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा प्रायोजित "न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना" में प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण कार्य किया जा रहा है। अभी तक 32 लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जा चुके हैं।

लघु वनोपज के 2 नए उत्पाद परीक्षण के बाद होंगे लॉन्च

वन मंत्री डॉ. शाह ने म.प्र. लघु वनोपज प्र-संस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र बरखेड़ा पठानी द्वारा तैयार किए जा रहे कोल्ड ड्रिंग्स, मधु कोला और जम्मू कोला के सैम्पल को बहुत अच्छा बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस नए उत्पाद का परीक्षण के बाद व्यापक स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित की जाए। वन मंत्री डॉ.शाह ने कहा कि इन दोनों उत्पाद की विश्वसनीयता का परीक्षण और अन्य प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद उत्पादों को लॉन्च किया जाए।

बैठक में बताया गया कि इन दोनों उत्पाद को मार्केट में लॉन्च किए जाने से इसका विपणन शीर्ष स्तर पर पहुँचेगा। प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री आर.के. गुप्ता सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

सहकारी समितियों के कर्मचारियों को नियमित और समय पर मिलेगा वेतन - सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया

भोपाल। प्राथमिक सहकारी साख समितियों के कर्मचारियों को प्रतिमाह मानदेय/वेतन का भुगतान होगा। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने नियमित और समय पर मानदेय/वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। सहकारी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि-मण्डल ने सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया से उनके निवास कार्यालय पर भेंट कर माँगों के संबंध में चर्चा की। सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि जिन मार्गों पर निर्णय लिया गया है, उनके आदेश एक सप्ताह में जारी कर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि महासंघ की अन्य माँगों पर विचार कर निर्णय करने के निर्देश दिये गये हैं। सहकारिता आयुक्त श्री संजय गुप्ता, एम.डी. अपेक्स बैंक श्री पी.एस. तिवारी, एम.डी. आवास संघ श्री ए.एस. सेंगर, सहकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री बी.एस. चौहान, कार्यवाहक अध्यक्ष श्री लखन यादव, उपाध्यक्ष श्री अशोक राय, महासचिव श्री रमेश चौबे, सचिव श्री रामकुमार दांगी, प्रवक्ता श्री शफीक खान और श्री वीरेन्द्र राजपूत चर्चा के दौरान उपस्थित थे।

कोटवार प्रशासन और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी : सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया

भोपाल : कोटवार गाँव में जनता और प्रशासन के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह बात सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने कही। मंत्री डॉ. भदौरिया नीलम पार्क में मध्यप्रदेश कोटवार चौकीदार के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि कोटवार की गाँव में महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्व, पुलिस, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के कार्य में कोटवार सहयोग करते हैं।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि कोटवार संघ के माँग-पत्र को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्व मंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें पूरा करने का अनुरोध करेंगे। महासम्मेलन में संघ के पदाधिकारियों ने मंत्री डॉ. भदौरिया को मांग-पत्र सौंप कर उन्हें पूरा करने का अनुरोध किया।

प्रदेश में इजरायल के सहयोग से बनेंगे कृषि उत्कृष्टता केंद्र

पर्यटन, सिंचाई, व्यापार-उद्योग क्षेत्र में भी बढ़ेगा साझा सहयोग
मुख्यमंत्री श्री चौहान से इजरायल के काउंसलेट जनरल श्री कोबी शोशानी ने की सौजन्य भेंट

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से इज़राइल के काउंसलेट जनरल श्री कोबी शोशानी ने मध्यप्रदेश प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री निवास से बड़ी झील का दृश्य देख आनंदित भी हुए।

काउंसलेट जनरल श्री शोशानी ने मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुए विकास की सराहना की। उन्होंने कृषि सहित सिंचाई, उद्योग, व्यापार-वाणिज्य क्षेत्रों में इजराइल द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वर्तमान में प्रदेश में मालनपुर और मंडीदीप में इजराइल की कंपनियों के कुछ प्रतिष्ठान कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इजराइल के सहयोग से मध्यप्रदेश इन क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए तैयार है। इजराइल द्वारा प्राप्त सुझाव पर भी विचार कर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इजराइल द्वारा प्रदेश के 2 जिलों छिंदवाड़ा और मुरैना में संतरे एवं सब्जी उत्पादन के प्रकल्प से जुड़ने की पहल की प्रशंसा की। सिंचाई क्षेत्र में भारत और इजराइल द्वारा मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में जल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से दोनों देश जल प्रबंधन के अन्य संभावित क्षेत्रों में सहयोग के लिए तत्पर हैं। मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को भी इजराइली कम्पनियों के सहयोग से बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को श्री शोशानी ने बताया कि इजराइल का भारत में 29 कृषि उत्कृष्टता केन्द्रों में से दो केन्द्र मध्यप्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें छिंदवाड़ा में संतरा उत्पादन और मुरैना में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इजराइल में एक पखवाड़े के विशेषण पाठ्यक्रम में मध्यप्रदेश के कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी लाभान्वित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन-बेतवा परियोजना के क्रियान्वयन से बुंदेलखंड क्षेत्र का कायाकल्प होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" के सिद्धांत और इजरायल की कृषि शैली से मध्यप्रदेश प्रेरित है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास होंगे।

बहुत पसंद आया मध्यप्रदेश

इजराइल के काउंसलेट जनरल ने कहा कि उन्हें भोजपुर और भीमबेटका के भ्रमण से बहुत आनंद मिला। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित ट्राइबल म्यूजियम को देखकर भी प्रसन्नता हुई। भोपाल की बड़ी झील बहुत खूबसूरत है।

पर्यटन क्षेत्र को देंगे बढ़ावा

इजराइल के काउंसलेट जनरल ने कहा कि यह वर्ष भारत और इजराइल के 30 वर्ष के मधुर संबंधों के उत्सव का वर्ष है। इजराइल से अधिक संख्या में पर्यटक मध्यप्रदेश आएँ, इसके प्रयास होंगे। मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों में वह आकर्षण है जो पूरे विश्व के पर्यटकों को यहाँ खींच सकता है।

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय कुमार शुक्ला उपस्थित थे।

पीएम किसान योजना के हितग्राही ई-केवायसी की कार्यवाही 31 तक पूर्ण कराएं

विदिशा : भारत सरकार द्वारा पीएम किसान योजनांतर्गत चयनित हितग्राहियों के ई-केवायसी संबंधी कार्यवाही 31 मार्च तक पूर्ण कराने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। डिप्टी कलेक्टर सुश्री अनुभा जैन ने बताया कि हितग्राहियों के ई-केवायसी की सुविधा पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर एवं पीएम किसान एप पर नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधाा के माध्यम से आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवायसी की कार्यवाही पूर्ण की जानी है। इसके अतिरिक्त सीएससी केन्द्रों के माध्यम से भी ई-केवायसी की कार्यवाही हितग्राही द्वारा ओटीपी या बायोमैट्रिक से पूर्ण की जा सकती है। सीएससी केन्द्र के माध्यम से ई-केवायसी की शुल्क 15 रूपये नियत की गई है। अतः पीएम किसान योजना के हितग्राहियों हेतु ई-केवायसी कार्यवाही 31 मार्च तक पूर्ण कराया जाना अति आवश्यक है। ई-केवायसी कार्यवाही के उपरांत ही पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। उपरोक्त का हर स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश संबंधितों को प्रसारित किए गए हैं। ताकि नियत तिथि उपरांत हितग्राहियों को योजना का निरंतर लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े।

गर्मी में तीसरी फसल मूंगफली उगाएं

खेत का चुनाव– मूंगफली की खेती गहरी काली मिट्टी छोडक़र सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। मूंगफली के अधिक उत्पादन हेतु जिस मिट्टी में कैल्शियम एवं जैव पदार्थों की अधिकता युक्त दोमट एवं बलुई दोमट अच्छी होती है। जिसका पीएच मान 6-7 के मध्य को उपयुक्त रहती है।

बीज का चयन

बीज के लिए चयनित फलियों में से बुवाई के लगभग 1 सप्ताह पहले दाने हाथ या मशीन से निकाल लें।

बीज उपचार

बीज जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 2-3ग्राम/कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करें। प्रारंभिक अवस्था में फसल को कीटों से बचाने के लिए 2.5 मिली/किग्रा बीज की दर से क्लोरोपायरीफास 20 ईसी से उपचारित करें एवं राइजोबियम एवं पीएसबी 10 मिली/ किग्रा बीज की दर से बीज उपचारित कर बुवाई करें।

बुवाई

मूंगफली की खेती खरीफ, रबी एवं ग्रीष्म ऋतु में की जाती है गर्मी (जायद) की फसल की बुवाई 15 मार्च के अंदर हो।

बीज दर

झुमका (गुच्छेदार) किस्मों के लिए सामान्यत: 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर जबकि फैलने वाली एवं अर्ध फैलने वाली किस्मों के लिए 80 किलोग्राम प्रति हे. पर्याप्त होती है। दूरी- झुमका (गुच्छेदार)

किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेमी एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं इसी प्रकार फैलने वाली एवं अर्ध फैलने वाली के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेमी एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं।

किस्में

जायद मौसम के लिए किस्में–जीजी-20, टीजी-37 ए, टीपीजी- 41, जीजी-6, डीएच – 86, जीजेजी-9 इत्यदि।

खाद एवं उर्वरक

अच्छी पैदावार हेतु 50 क्विंटल प्रति हे. सड़ा गोबर खाद का प्रयोग करें। उर्वरक एनपीके 20:60:20 किग्रा प्रति हे. पर्याप्त होता है। इनके साथ 25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का आधार खाद के रूप मे प्रयोग करने से उपज में 20-22 प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई है।

सिंचाई

गर्मी में मूंगफली की खेती के लिए भूमि के अनुसार 5-6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। रबी की सरसों, चना, मसूर, मटर, आदि फसलों की कटाई के बाद एक जुताई कर पलेवा करके खेत तैयार कर बुवाई करें। पहली सिंचाई अंकुरण के बाद (12-15 दिन), दूसरी सिंचाई 25-30 दिन बाद, तीसरी सिंचाई बुवाई के 40-45 दिन बाद, चौथी सिंचाई 55-60 दिन बाद और अंतिम सिंचाई बुवाई के 70-80 दिन बाद करें।

खरपतवार नियंत्रण

निदाई-गुड़ाई खुरपी या हैंड हो से कर सकते हैं। खड़ी फसल में इमेजाथायपर या क्युजालोफाप इथाइल की 100 मि.ली./ हे. सक्रिय तत्व का 400-500 लीटर पानी में घोल बनाकर 15-20 दिन बाद प्रयोग करें साथ ही एक निराई गुड़ाई बुवाई के 25-30 दिन बाद अवश्य करें, जो कि तंतु (पैगिंग) प्रक्रिया में लाभकारी होता है।

खुदाई

जब पत्तियों का रंग पीला पडऩे लगे एवं फलियों के अंदर का एनिन का रंग उड़ जाए तथा बीजों के खोल रंगीन हो जाए तो खेत में हल्की सिंचाई कर लें एवं पौधे से फलियों को अलग कर लें और खुदाई के बाद धूप सुखा कर रखें।

भंडारण

मूंगफली की उचित भंडारण एवं अंकुरण क्षमता को बनाए रखने हेतु कटाई के बाद सावधानीपूर्वक सुखायें। भंडारण करते समय पके हुए दानों में नमी की मात्रा 8-10 प्रतिशत से अधिक नमी होने पर मूंगफली में पीली फफूंद द्वारा अफ्लाटॉक्सिन नामक तत्व पैदा होता है जो पशुओं एवं मानव के लिए हानिकारक होता है। यदि मूंगफली को तेज धूप में सुखाया जाता है तो अंकुरण का हास्य होता है।

पेपर मैसी वर्किंग समिति से जुड़ी जनजाति की महिलाओं की बदली तकदीर

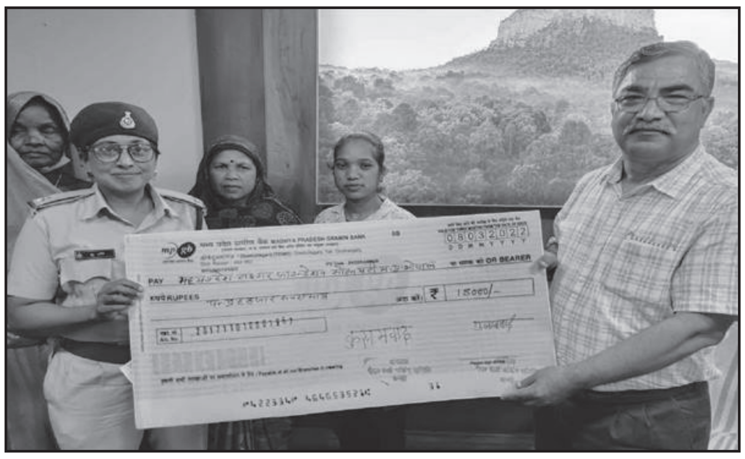

भोपाल : मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी की ऋण राशि से रातापानी अभयारण्य के अंतर्गत पेपर मैसी वर्किंग समिति से जुड़ी जनजाति की 10 महिलओं का जीवन स्तर सुधरा है। इन्हें सालाना औसतन 70 से 75 हजार की आमदनी होने लगी है।

जनजाति की यह महिलाएँ पहले 14 किलोमीटर पैदल चलकर जंगल से लकड़ी काट सिर पर रख बमनई से औबेदुल्लागंज बेचने आया करती थी। वन विभाग की वन रक्षक सुश्री शशि अहिरवार ने इन महिलाओं को दिक्कतों से निजात दिलाने और जंगल बचाने के उद्देश्य से वरिसा विभागीय अधिकारियों के समक्ष ग्राम बमनई में पैपर मैसी वर्किंग समिति बनाने प्रस्ताव रखा। समिति और महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिलाया। प्रशिक्षण बाद सामग्री तैयार होने लगी पर सामग्री विक्रय का कोई जरिया नहीं रहा।

वन मंडल औबेदुल्लागंज ने इन महिलाओं को विभिन्न स्थलों पर हुए आयोजन में मंच प्रदान किया। इन महिलाओं के कौशल उन्नयन के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाया गया। इस बीच पिछले 2 साल में कोविड-19 के कारण इन महिलाओं द्वारा तैयार सामग्री को बेचने से वंचित रहीं। वन विभाग की म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी ने आगे आकर इस समिति को 25 हजार रूपये का ऋण उपलब्ध कराया। इससे महिलाओं ने पुन: कार्य प्रारंभ किया और वन मेले में स्टाल लगा लिया। इससे इन महिलाओं की आमदनी में इजाफा हुआ।

पेपर मैसी वर्किंग समिति की महिलाओं ने शुक्रवार को भोपाल आकर प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं फाउंडेशन सचिव श्री जसबीर सिंह चौहान से भेंटकर ऋण राशि का 60 प्रतिशत राशि का चैक भेंट किया। श्री चौहान ने जनजाति की महिलाओं द्वारा की गई मेहनत की प्रशंसा करते हुए महिलाओं को आगे आने का आव्हान किया। समिति की महिलाओं ने बताया कि समिति को जो लाभ मिलता है उसका 5 प्रतिशत ईको विकास समिति बमनई को दिया जाता है।

नल जल योजनाओं के संचालन का जिम्मा अब महिला समूहों को

भोपाल : जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलों में भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एण्ड रिसर्च के माध्यम से ग्राम पंचायतों के ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता ग्राम के महिला स्वसहायता समूह नलजल योजनाओं का संचालन संधारण करेंगे l इससे ग्राम की नलजल प्रदाय योजना से 100 प्रतिशत घरों को सुचारू रूप से शुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की पूर्ति सुनिश्चित हागी। पेयजल आपूर्ति में बाधा के कारण सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को ही होता है, महिलाओं की सहभागिता से योजनाऐं अच्छे से संचालित होगी। जब तक ग्राम के निवासियों में नलजल प्रदाय योजना के प्रति स्वामित्व का भाव नहीं होगा नलजल योजना सुचारू रूप से संचालित नहीं की जा सकेगी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य उसकी संकल्पना, ग्राम का जल बजट कैसे बनाया जाता है और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

लहसुन उत्पादन में मध्यप्रदेश...

उन्होंने बताया कि देश में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 29 लाख टन लहसुन उत्पादन हुआ था वह लगभग 3 लाख हेक्टेयर बढक़र 31 लाख टन से अधिक हो गया है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि राज्यों के अनुरोध पर लहसुन सहित उन कृषि और बागवानी जिंसों की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्य करती है जो नाशवान प्रकृति की होती हैं। एमआईएस इन जिंसों के उत्पादकों को बम्बर आवक के दौरान जब पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में उत्पादन में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है या प्रचलित मंडी कीमतों में 10 प्रतिशत की कमी होती है, तो दबाव में बिक्री करने से बचाने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

श्री तोमर ने बताया कि लहसुन सहित बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रही है। एमआईडीएच के तहत, प्रकंद मसालों के क्षेत्रफल में विस्तार के लिए, सहायता प्रदान की जाती है जिसमें एक किस्त में प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर की खेती के लिए 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर (अर्थात् अधिकतम 12,000 रु. /हेक्टेयर) 40 प्रतिशत लागत मानदंड की दर से लहसुन के लिए सहायता दी जाती है।

उन्होंने बताया कि सरकार एमआईडीएच योजना चल रही है, जिसमें क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन/एकीकृत पोषक प्रबंधन, जैविक खेती, जल संसाधन संरचनाओं के निर्माण, फसलोपरांत प्रबंधन, बाजार प्रांगणों का विकास, शीत भंडारण की स्थापना, मानव संसाधन विकास आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से लहसुन और प्याज सहित बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने योजना बनाई गई है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

ड्रोन इस्तेमाल में बनायेंगे ...

ड्रोन स्कूलों के जरिए साल भर में ढ़ाई हजार ड्रोन पायलट होंगे तैयार : केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि भारत किसी भी देश का फोलोअर नहीं लीडर बने। इसी संकल्पना को साकार करने के लिये ड्रोन को गाँव-गाँव और घर-घर में पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत 11 दिसम्बर को प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। खुशी की बात है कि मात्र 90 दिन के भीतर सभी औपचारिकताएँ पूरा करने के बाद आज ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल शुरू हो गया है। श्री सिंधिया ने बताया कि इस ड्रोन स्कूल में हर माह 40 से 50 बच्चों को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार साल भर में लगभग 500 युवा ड्रोन पायलट के रूप में तैयार होंगे। ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त युवा हर माह औसतन 30 हजार रूपए की आय आसानी से अर्जित कर पायेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के पाँचों ड्रोन स्कूल शुरू होने पर साल भर में लगभग ढ़ाई हजार ड्रोन पायलट तैयार होंगे। श्री सिंधिया ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश वर्तमान में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल में देशभर के अग्रणी राज्यों में से एक है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सभी शासकीय कैंटीन का संचालन स्व-सहायता समूहों...

इस कैफे के साथ हमारी बहनें भी सफलता के नये शिखर पर पहुँचे, यही कामना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर स्व-सहायता समूह की बहन की मासिक आमदनी कम से कम 10 हजार रूपये हो। उन्होंने कहा कि आनंद की बात है कि आज 127 दीदी कैफे खुलने से एक ही दिन में हमारी हजारों बहनें रोजगार से जुड़ गई हैं। स्व-सहायता समूह की बहनों की खुशी हमारे लिए सच्चा सुख है।

मानव संसाधन हेतु आउट सोर्स कर्मचारियों का प्रशिक्षण

भोपाल। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर में आउटसोर्स के माध्यम से उनकी मांग अनुसार 28 सशस्त्र गनमेन/सुरक्षा गार्ड एवं एक सिविल इंजीनियर को उनके कार्य दायित्व पर आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अपेक्स बैंक के एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के माननीय सहकारिता मंत्री डॉ.अरविंद सिंह भदौरिया जी की मंशानुरुप मध्यप्रदेश में सहकारी आन्दोलन की प्रगति के नये सोपान स्थापित करने हेतु अग्रसर अपेक्स बैंक ग्वालियर की संभागीय शाखा के सिटी सेंटर एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन श्री पी.एस.तिवारी, प्रबंध संचालक, श्री आर0एस0चंदेल, सहायक महाप्रबंधक एवं श्रीमती अनुभा सूद, उपायुक्त, सहकारिता, ग्वालियर ने किया। इस अवसर पर संभागीय शाखा प्रबंधक श्री सुशील कुशवाह, सहायक प्रबंधक एस0के0जैन के साथ बैंक के अनेक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ अनेक गणमान्य लोग व अमानतदार उपस्थित हुए।

प्रबंधक संचालक श्री तिवारी ने इस अवसर पर सभी से अपेक्षा की कि ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के हृदयस्थल "सिटी सेंटर" में शुरु हो रहे एक्सटेंशन काउंटर के माध्यम से हमारी अनेक जनकल्याणकारी एवं आकर्षक ऋण योजनाओं का लाभ अपने व्यवसाय संवर्धन में आमजनों द्वारा अवश्य प्राप्त किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि अपेक्स बैंक प्रदेश का एकमात्र बैंक है जो अपने वरिष्ठ नागरिक अमानतदारों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज प्रदान करने के साथ 8 प्रतिशत पर समस्त ऋण वितरित कर प्रदेश की जनता की सेवा को तत्पर है।

आजीविका विकास के लिए स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों का भ्रमण

उज्जैन- सहकारिता मन्त्रालय भारत शासन कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सहकारी शिक्षा क्षेत्रीय परियोजना उज्जैन द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को आजीविका विकास के लिए एक दिवसीय भ्रमण करवाया गया जिसमें स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सर्वप्रथम धार जिले के ग्राम तिरला में आजीविका मिशन केंद्र का भ्रमण करवाया गया क्योंकि वहां पर बहुतायत में सुरजना पेड़ है जिसका उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने सुरजना फली का पाउडर बनाने में प्रयोग किया उस पाउडर के क्या लाभ हैं उसके बारे में आजीविका मिशन के प्रभारी श्री राकेश सिंह तोमर ने विस्तृत जानकारी देते हुए पाउडर के उपयोग एवं लाभ के बारे में जानकारी दी साथही उन्होंने कहा की आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से हैं आप भी अपने यहां खाली पड़ी भूमि पर सुरजना के पौधे लगाएं जिसे से पर्यावरण शुद्ध होगा एवं आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

कुक्षी ब्लॉक के ग्राम सस्तीपुर मे मसाला इकाई का भ्रमण करवाया गया वहां कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मिर्च , हल्दी एवं धनिया पाउडर बनाने की इकाई का अवलोकन करवाया गया वहां की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मिर्ची , धनिया तथा हल्दी पाउडर बनाकर आस-पास के गांव में विक्रय कर अतिरिक्त आय अर्जित की एवं उसके बाद मनावर ब्लॉक में आजीविका मिशन द्वारा सेनेटरी नैपकिन निर्माण इकाई का अवलोकन किया तथा वहां के निदेशक ने इकाई की विस्तृत जानकारी दी साथ ही सेनेटरी नैपकिन के विक्रय एवं निर्माण संबंधी जानकारी भी दी साथ ही कहा आप अपने क्षेत्र में उपरोक्त सभी कार्य कर सकती हैं जिन क्षेत्रों का भ्रमण कर आई हैं वहा चल रहे कार्य करेंगी तो आपका आना सार्थक होगा यह बात स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को वहां के निदेशक ने कही उक्त भ्रमण कार्यक्रम में प्रभारी परियोजना अधिकारी चंद्रशेखर बैरागी एवं सहकारी शिक्षा प्रेरक प्रेम सिंह झाला कृपा वेलफेयर सोसाइटी के निदेशक सुनील फादर एवं श्री गोपाल गुप्ता विशेष रुप से थे।

एक जिला एक उत्पाद के तहत धनिया प्रसंस्करण ईकाई स्थापित कर खेती को उद्योग बनाया किसान नंदकिशोर धाकड ने

नीमच। नीमच जिले के ग्राम भोलियावास के किसान नंदकिशोर धाकड ने एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का लाभ लेकर धनिया की प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना कर खेती को उद्योग बना दिया है। अब वे धनिया का प्रसंस्करण कर, पाउडर बनाकर उसकी पेकेजिंग व मार्केटिंग कर अधिक मुनाफा कमा रहे है। उन्होंने खेती को उद्योग बना लिया है। नंदकिशोर की प्रसंस्करण ईकाई में 8 से 10 अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है।

नीमच जिले के विकासखंड नीमच के ग्राम भोलियावास के किसान नंदकिशोर धाकड व्दा रा 2.00 हैक्टेनयर में धनिया की खेती की जा रही थी परन्तु केवल धनिया के उत्पा दन से उतना मुनाफा नही होने से कृषक की रूची धनिये के प्रसंस्करण एवं निर्यात की ओर बढ़ने लगी । परन्तु उन्हेंव पूर्व में प्रसंस्करण एवं निर्यात के क्षैत्र में कोई अनुभव नही होने से उन्हो ने उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया और प्रधानमंत्री सूक्ष्म् खाद्य उन्नयन योजना का लाभ लिया। कृषक नंदकिशोर धाकड़ ने एक जिला एक उत्पाद योजना अन्त र्गत धनिया प्रसंस्करण इकाई की स्थाापना के लिए डीपीआर तैयार करवा कर PM-FME योजना में ऑनलाईन आवेदन किया।

किसान नंदकिशोर धाकड को बैंक द्वारा 26 लाख का लोन वितरित किया गया, कृषक नंदकिशोर को प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु 35 प्रतिशत तक ऋण अनुदान का लाभ 9 लाख रूपये अनुदान मिला। कृषक नंदकिशोर वर्तमान में अपनी धनिया प्रसंस्करण इकाई में धनिया से धनिया पाउडर, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग कर रहे हैं। नंदकिशोर द्वारा 2 माह में कुल 10 क्विंटल धनिया पाउडर का प्रसंस्करण किया है। कृषक द्वारा 80 से 90 रूपये प्रति किलो की दर से 80 हजार रूपये में 10 क्विंटल धनिया खरीदा और बीस रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रसंस्करण एवं पैकिंग पर 20 हजार रूपये खर्च हुए। प्रसंस्कृ्त उत्पाद को 140 से 150 प्रति किलो की दर से एक लाख 50 हजार रूपये में बेचा। इस प्रकार कृषक नंदकिशोर को 50 हजार रूपये का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ है। कृषक नंदकिशोर द्वारा भविष्य में जिले में उत्पादित निर्यात योग्य किस्मों ACR-2 एवं Gujrat-3 के प्रसंस्करण में रूची ली जा रही हैं, जिससे निर्यात की संभावनाएं बढ़ने से उसे होने वाला मुनाफा भी अधिक होगा।

गेहू उपार्जन हेतु 16311 किसानों ने कराया पंजीयन

उमरिया - जिला आपूर्ति अधिकारी बी एस परिहार ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2022- 23 समर्थन मूल्य पर गेहू उपार्जन हेतु जिले मे बनाए 35 केंद्र के माध्यम से 16311 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जिसमें मानपुर के 9949 किसानो, चंदिया के 2881 किसानों ने, बिलासपुर के 1435 किसानो ने, बांधवगढ़ के 685 किसानों ने, पाली के 526 किसानों ने, पाली के 443 किसानों ने, करकेली के 443 किसानों ने तथा नौरोजाबाद के 392 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है।

माह मार्च 2022 में राज्य सहकारी संघ में निरंतर प्रशिक्षण

भोपाल। आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत आजादी के 75 वें अमृत महोत्सव की बेला में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा दिनांक 2 मार्च से 16 मार्च 2022 तक सहकारी आंदोलन को सशक्त एवं प्रभावी बनाने हेतु सहकारिता विभाग के स्तम्भ प्रदेश के सहकारी निरीक्षकों, नागरिक सहकारी बैंकों के सहायक प्रबंधकों एवं लेखाधिकारियों, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के गोदाम प्रभारियों, सहकारिता विभाग की मुख्यालय स्थित समस्त महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों पर विभिन्न तिथियों में प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन जी के मार्गदर्शन में प्रभावी प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

दिनांक 2 से 4 मार्च एवं 7 से 9 मार्च 2022 तक दो सत्र में सहकारी निरीक्षकों हेतु गबन धोखाधडी एवं अंकेक्षण, विभागीय कार्य निष्पादन विषय पर आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के 31 प्रतिभागी उपस्थित रहे, जो आगामी माहों में भी निरन्तर आयोजित किये जाना है।

दिनांक 5 मार्च एवं 12 मार्च 2022 को प्रदेश के समस्त नागरिक सहकारी बैंकों के सहायक प्रबंधकों एवं लेखाधिकारियों को बैंक के कार्य निष्पादन, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमावली अनुसार कार्यो को संपादन करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों एवं अथिति व्याख्याता द्वारा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें 52 प्रतिभागी सम्मिलित रहें।

दिनांक 8 मार्च 2022 अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के चहुंमुखी विकास एवं कार्य संतुलन पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण को सारगर्भित एवं उपयोगी सिद्ध करने हेतु डा. पूजा मेहता, मोटिवेशनल वक्ता एवं अन्य वक्ताओं द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें 50 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया।

दिनांक 7 मार्च से 9 मार्च, 10 मार्च से 12 मार्च एवं 14 मार्च से 16 मार्च 2022 तक म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के गोदाम प्रभारियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण गोदाम भंडारण के आधुनिक तकनीक, रख रखाव, भंडारण को बचाने के उपाय, वर्तमान परिवेश में प्याज, लहसून, फल सब्जियों के भंडारण की आधुनिक पद्धति पर व्याख्यान/प्रशिक्षण प्रख्यात विद्वानों के माध्यम से दिया गया। प्रशिक्षण में 140 प्रतिभागियों ने ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त किया।

दिनांक 10 एवं 11 मार्च 2022 को पैक्स समितियों के प्रशासकों के लिए एक–एक दिवसीय प्रशिक्षण पैक्स प्रशासकों के अधिकार कर्तव्य, आयुक्त सहकारिता द्वारा समय–समय पर परिपत्रों के माध्यम से दिए गये दिशा निर्देश का परिपालन, प्रशासक क्या करें क्या ना करें? रिटर्नस क्लेम कैसे प्रस्तुत करें। किस प्रकार अंकेक्षण करवाये। समर्थन मूल्य खरीदी में हुई क्षति पूर्ति हेतु आर्बीटेशन, दावा, प्रक्रिया, वित्तदायी बैंक, जिला प्रशासन एवं सहकारिता विभाग में समन्वय एवं सम्पूर्ण कार्यो में प्रशासक की भूमिका पर प्रशिक्षण 163 प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया गया।

MP STATE COOPERATIVE UNION LTD.
E-8/77, SHAHPURA, TRILANGA ROAD BHOPAL - 462039
Email: - rajyasanghbpl@yahoo.co.in
Website: WWW.mpscu.in Tel.:- 0755-2926160

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR EMPANELMENT OF MANPOWER OUTSOURCING AGENCY

Expression of Interest (EOI) is invited for empanelment of Man-power Out Sourcing Agency.
The detailed terms and conditions of the EOI are given on our website www.mpscu.in. Interested parties may download EOI document from website.
The interested agencies may apply as per the directives mentioned in the EOI document on or before 28.03.2022 by 5 P.M. in the office of under signed. The Managing Director reserves the right to cancel this EOI without assigning any reason.

Managing Director

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित
(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)
माध्यम - ऑनलाईन
योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह ऑनलाईन आवेदन/
प्रवेश की अंतिम तिथि – 30 अप्रैल 2022
कुल फीस - 20200/-
ऑनलाइन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के
पोर्टल www.mpscuonline.in पर विजिट करें।

संपर्क :-
म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158
Website-www.mpscu.in, Web Portal-www.mpscuonline.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001
फोन- 0761-2341338 मो. 9424782856 , 8827712378
Email - ctcjabalpur@gmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव
जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन – 471201
फोन- 07685-256344 मो. 9630661773
Email - ctcnowgong@gmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।